

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल को वनियमिति करने की अनुमति देना

प्रलिमिस के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय, महत्त्वपूर्ण नियम, संवैधानिकी पीठ, केंद्र-राज्य संबंध, औद्योगिक अल्कोहल, 7वीं अनुसूची, उत्पाद शुलक, वस्तु और सेवा कर (GST)

मेन्स के लिये:

भारत में संघवाद, सर्वोच्च न्यायालय के महत्त्वपूर्ण नियम, सहकारी संघवाद, संघवाद के लिये चुनौतियाँ, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संवधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से फैसला सुनाया करिज्यों को औद्योगिक अल्कोहल को वनियमिति करने का अधिकार है, इस फैसले में वर्ष 1990 के फैसले 1989 को खारज कर दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार के नियंत्रण का समर्थन किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिकी पीठ क्या है?

- परचियः
 - सर्वोच्च न्यायालय में संवधान पीठ में पाँच या उससे अधिक न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें केवल विशिष्ट कानूनी मामलों के लिये ही आमंत्रित किया जाता है। ये पीठें कोई नियमिति प्रक्रिया नहीं हैं।
- गठन के लिये परस्थितियाँ:
 - अनुच्छेद 145(3): अनुच्छेद 143 के तहत महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों या संदर्भों से जुड़े मामलों पर नियमिति के लिये आवश्यक न्यायाधीशों की न्यूनतम सख्त्या पाँच है।
 - विवादित नियम: जब विभिन्न तीन न्यायाधीशों की पीठों से परस्पर विवादित नियमिति आते हैं, तो मुद्दे को हल करने के लिये एक विशेष संवधान पीठ का गठन किया जाता है।

औद्योगिक अल्कोहल:

- औद्योगिक अल्कोहल मूलतः अशुद्ध अल्कोहल है जिसका उपयोग औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है।
- इथनॉल में बैंजीन, परिडीन, गैसोलीन आदि जैसे रसायनों को मिलाने से (इस प्रक्रिया को विकृतीकरण कहा जाता है) यह औद्योगिक अल्कोहल में बदल जाता है, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो जाती है जो यह मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त हो जाता है।
- अनुप्रयोग: फार्मास्यूटिकल्स, इतर, सौंदर्य प्रसाधन और सफाई संबंधी तरल पदार्थों में उपयोग किया जाता है।
 - कभी-कभी इसका उपयोग अवैध शराब, सस्ते और खतरनाक नशीले पदार्थ के नियमिति में भी किया जाता है, जिनके सेवन से अंधापन और मृत्यु सहित गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं।

औद्योगिक अल्कोहल पर सर्वोच्च न्यायालय पीठ ने क्या फैसला दिया है?

- परभिषा का वस्तिरार: बहुमत वाली पीठ ने १९९० में वर्ष १९९० के फैसले को पलट दिया है, जिसमें "मादक शराब" की परभिषा को पीने योग्य शराब तक सीमित कर दिया गया था तथा राज्यों को औद्योगिक शराब पर कर लगाने से रोक दिया गया था।
- बहुमत की राय: खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि "नशीली शराब" में सरिफ मादक पेय या पीने योग्य शराब ही शामिल नहीं है। सभी प्रकार की शराब जो सारवजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इस परभिषा के अंतर्गत आती है।
 - न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कशिराब, **अफीम और नशीली दवाओं** जैसे पदार्थों का दुरुपयोग किया जा सकता है तथा फैसला सुनाया कि संसद मादक शराबों पर राज्य की शक्तियों को खत्म नहीं कर सकती है, और कहा कि "नशीली" का अर्थ "जहरीला" भी हो सकता है, जिससे वयापक वर्गीकरण की अनुमतिमिलती है।
- असहमतपूर्ण राय: न्यायमूरत बी.वी. नागरतना ने औद्योगिक अल्कोहल के वनियमन के संबंध में बहुमत के फैसले से असहमतव्यक्त की और तरक्की दिया कि केवल इसलिये कि "औद्योगिक अल्कोहल" का संभावित दुरुपयोग हो सकता है, प्रविष्टि ४ - सूची II को ऐसे "औद्योगिक अल्कोहल" को शामिल करने के लिये नहीं बढ़ाया जा सकता है।
 - राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल को वनियमित करने की अनुमति देने से अल्कोहल वनियमन के पीछे वधियाँ मंशा की गलत व्याख्या हो सकती है।

औद्योगिक अल्कोहल वनियमन पर केंद्र बनाम राज्यों के तरक्की:

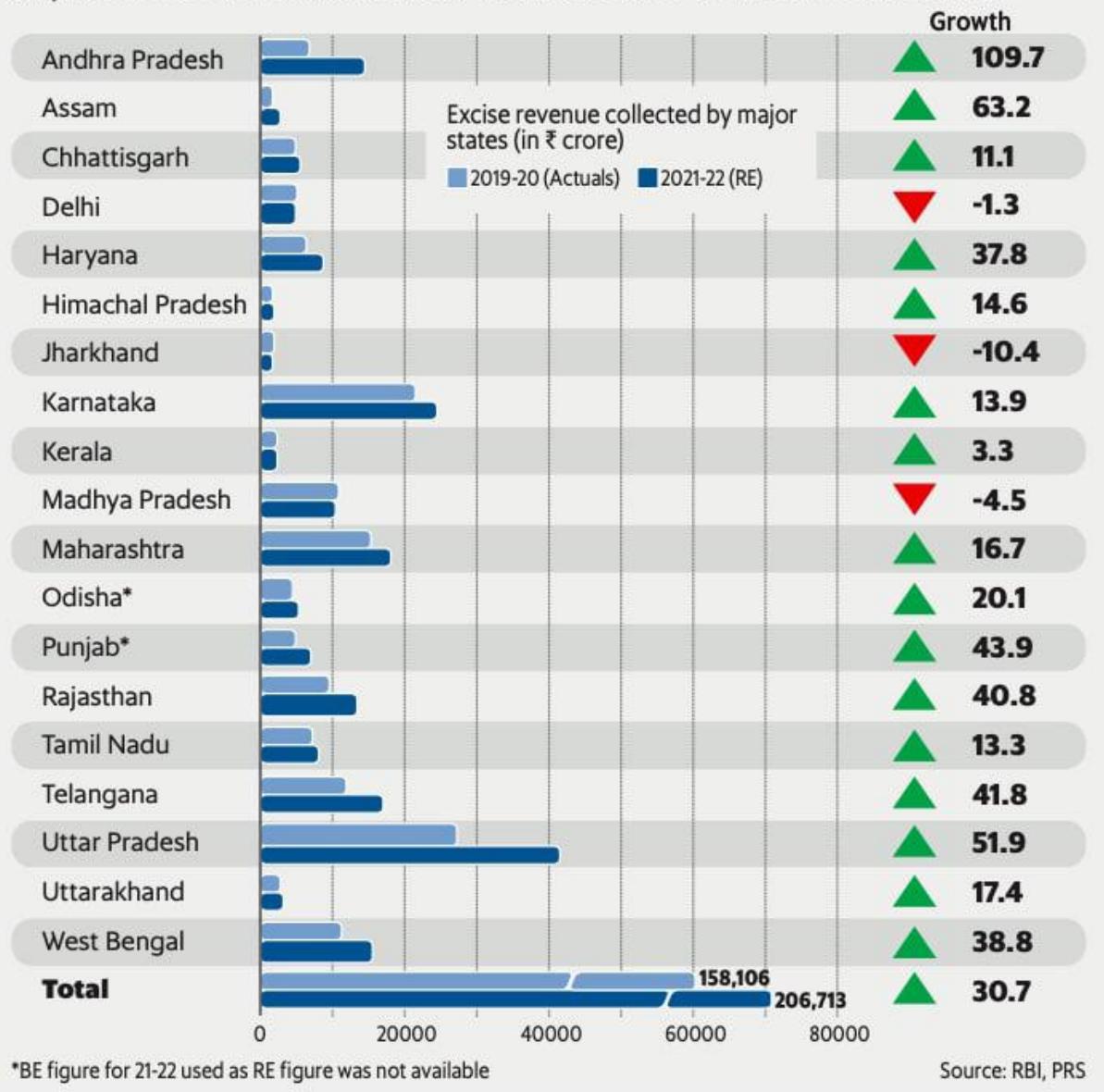
- केंद्र सरकार का तरक्की:**
 - औद्योगिक अल्कोहल को संघ सूची की प्रविष्टि ५२ के अंतर्गत "उदयोग" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे केंद्र को सारवजनिक हति में समझे जाने वाले उदयोगों को वनियमित करने की अनुमतिमिल गई है।
 - इसमें कहा गया है कि औद्योगिक शराब का व्यापार, वाणिज्य, आपूरत और वतिरण समवर्ती सूची की प्रविष्टि ३३(A) के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्रीय निगरानी की अनुमतिमिल देता है।
 - केंद्र का कहना है कि औद्योगिक शराब उदयोग (विकास और वनियमन) अधिनियम, १९६१ के अधिकार क्षेत्र में आती है, तथा दावा किया कि यह वनियमन के लिये "क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है"। इसलिये, राज्य इस विषय पर अपने नियमन लागू नहीं कर सकते।
 - केंद्र का तरक्की है कि औद्योगिक अल्कोहल ने वनियमन के "क्षेत्र पर अधिकार कर लिया है" जो उदयोग (विकास और वनियमन) अधिनियम, १९६१ के अधीन है। इसलिये राज्य इस विषय पर अपने कानूनों को लागू करने में असमर्थ हैं।
- राज्यों का तरक्की:**
 - राज्य सूची की प्रविष्टि ४ के अंतर्गत वनियमन के लिये तरक्की देने के साथ मदरि पर कर लगाने के अधिकार पर बल दिया गया, जिसमें औद्योगिक मदरि भी शामिल है।
 - राज्यों द्वारा अवैध उपभोग से निपटने और राजस्व उत्पन्न करने के लिये प्राधिकार बनाए रखने की आवश्यकता (विशेष रूप से GST के कार्यान्वयन के बाद) है।

राज्यों के लिये शराब पर कर लगाने का महत्व

- राजस्व सूचन:** शराब पर कर लगाना राज्यों के लिये राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के लिये वर्ष 2023 में करनाटक ने भारत नियमित शराब (IML) पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (AED) 20% तक बढ़ा दिया।
- वित्तीय नियमित:** महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य अपने राजस्व का एक प्रमुख हस्तिया शराब करों से प्राप्त करते हैं, जो उनके कुल उत्पाद शुल्क राजस्व का लगभग 30-40% है।
- लोक सेवाओं का वित्तिपोषण:** शराब पर कर का उपयोग स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित आवश्यक लोक सेवाओं के वित्तिपोषण के लिये किया जाता है।

THE GOLDEN GOOSE

Major states collected more than ₹2 trillion under state excise in 2021-22.



उद्योग (विकास और वनियमन) अधनियम, 1951

- उद्योग (विकास और वनियमन) अधनियम, 1951 भारत में औद्योगिक विकास और वनियमन के लिये वधिकि और वैचारकि ढाँचा प्रदान करता है।
- इस अधनियम के मुख्य उद्देश्य:
 - देश में उद्योगों के विकास को नियंत्रिति और नियंत्रिति करना,
 - नष्टिपक्ष संसाधन वतिरण को बढ़ावा देना,
 - आरथकि शक्ति संकेन्द्रण से बचना,
 - संतुलित एवं नियंत्रित औद्योगिक वस्तितार को महत्त्व देना।
- यह अधनियम केन्द्र सरकार को नमिनलखिति शक्तियाँ प्रदान करता है:
 - कुछ उद्योगों के उत्पादन, आपूरति और वतिरण को वनियमिति करना
 - नये उद्योगों की स्थापना पर प्रतबंध लगाना
 - उद्योगों को संचालन हेतु लाइसेंस प्रदान करना
 - आम लोगों के सर्वोत्तम हति में उद्योग नियमण और संचालन

- आर्थिक शक्तिको कुछ ही हाथों में केंद्रति होने से रोकने के लिये कदम उठाना

इसी तरह के अन्य मामले कौन से हैं?

- **चौधरी टीका रामजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 1956:**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने उदयोग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (IDRA) की धारा 18-G के तहत वशीष केंद्रीय अधिकार क्षेत्र का दावा करने वाली चुनौती के खलिफ गन्ना उदयोग को विनियमित करने वाले उत्तर प्रदेश के कानून को बरकरार रखा।
 - इस नियम से केंद्र सरकार के कानूनों की उपस्थिति में भी उदयोगों के संबंध में कानून बनाने के राज्यों के अधिकार की पुष्टि होने के साथ संघीय शासन के लिये मसिल कायम हुई।
- **सथिटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, 1989:**
 - इसमें सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि राज्य सूची की प्रविष्टि के अनुसार राज्यों की शक्तियाँ "मादक शराब" को विनियमित करने तक सीमित हैं, जो औदयोगिक शराब से अलग है।
 - मूलतः सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल केंद्र ही औदयोगिक अल्कोहल (जो मानव उपभोग के लिये नहीं है) पर शुल्क या कर लगा सकता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय वर्ष 1956 में चौधरी टीका रामजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में अपनी ही पूर्व संविधान पीठ के नियम पर विचार करने में वफिल रहा।

इस नियम का क्या प्रभाव होगा?

- **लंबति मुकदमे:** इस नियम से राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए सुरक्षात्मक करों या वशीष शुल्कों से संबंधित चल रहे मुकदमे प्रभावित होंगे क्योंकि पूर्व के नियमों में ऐसे शुल्कों पर रोक लगा दी गई थी।
- **राज्यों की नियामक शक्ति:** अब राज्यों के पास औदयोगिक अल्कोहल के विनियमन और कराधान का अधिकार है, जिससे राज्यों में विभिन्न कर व्यवस्थाएँ लागू होने की संभावना है।
- **राजसव सृजन:** राजसव स्रोतों को बढ़ाने के लिये राज्य इस नियम का लाभ (वशीष रूप से GST के बाद) उठा सकते हैं, क्योंकि पहले उन्हें औदयोगिक अल्कोहल पर कर लगाने से प्रतिविधि कर्या गया था।
- **उदयोग जगत का दृष्टिकोण:** उदयोग इस फैसले को सकारात्मक रूप से देख रहे हैं और उनका सुझाव है कि इससे भारत में नियमित विदेशी शराब (IMFL) क्षेत्र के लिये विनियामक नियंत्रण और कराधान स्पष्ट होने से नियमाताओं के लिये अस्पष्टता कम हो गई है।
- **परचालन लागत:** संभवतः राज्य औदयोगिक अल्कोहल पर कर बढ़ा सकते हैं, जिससे इस पर नियमित उदयोगों की परचालन लागत प्रभावित होगी, जिससे मूल्य नियंत्रण में असमानता पैदा हो सकती है।

निषिकरण

- सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले से राज्यों को औदयोगिक शराब को विनियमित करने का अधिकार मिलने से उन्हें कर लगाने तथा उत्पादन और वितरण पर स्थानीय नियंत्रण बढ़ाने की अनुमति मिल गई है।
- यह नियम GST के बाद राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करता है, अबैध उपभोग को रोकने के लिये सख्त विनियमन को सक्षम बनाता है तथा इससे स्थानीय लोक स्वास्थ्य प्रभावों के प्रबंधन में राज्यों के विधायी अधिकारों पर प्रकाश पड़ता है।

प्रश्नोत्तरी के लिए जवाब देने के लिए इसे उत्तर देना चाहिए।

प्रश्न: भारत में राज्यों के राजसव सृजन एवं लोक स्वास्थ्य प्रबंधन के आलोक में औदयोगिक अल्कोहल के विनियमन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के नियंत्रणों पर चर्चा कीजिये।